भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2760
जिसका उत्तर मंगलवार 01 अगस्त, 2017 को दिया जाना है

खर्च न की गई राशि

2760. श्री अनंतकुमार हेगड़े:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सरकार संचालित कई आर्थिक, व्यावसायिक एवं औद्योगिक संस्थाओं के पास खर्च नहीं की गई राशि की बड़ी मात्रा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त धनराशि की पहचान की है; और

(घ) यदि हां, तो इस अप्रयुक्त राशि की मात्रा कितनी है तथा उक्त राशि का देश की विकास-योजनाओं में अब तक उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) की भूमिका इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई)/स्वायत्त निकायों (एबी) के प्रशासन तक सीमित है। तथापि, भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकार द्वारा संचालित कोई भी वित्तीय, व्यावसायिक और औद्योगिक संस्थान नहीं है।

(ग) और (घ): प्रश्न नहीं उठता।

******